## पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0

## राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को यू0एस0 तोमर को बर्खास्त करने के लिए पत्र भेजा राज्य सरकार यू0एस0 तोमर को कुलसचिव पद से बर्खास्त करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करे - श्री नाईक

लखनऊ: 3 अगस्त, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति डाँ0 ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने डाँ0 ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिव (निलम्बित) श्री यू०एस० तोमर को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार कुलसचिव (निलम्बित) श्री यू०एस० तोमर को बर्खास्त करने के संबंध आवश्यक आदेश पारित करे।

श्री यू०एस० तोमर कुलसचिव डाँ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ पर आरोप थे कि (1) मा० उच्चतम न्यायालय में संस्थित एस०एल०पी० (सिविल ९०४८/२०12 पाश्र्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम ए०आई०सी०टी०ई० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 13 दिसम्बर, २०12) जिसमें सम्बद्धता की अन्तिम तिथि 15 मई के बाद 44 कालेजों को जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सम्बद्धता प्रदान किया जाना, (2) सत्र २०13-14 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रवेश देने के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुलसचिव, डाँ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा नियमों के विपरीत सम्बद्धता आदेश निर्गत करना, (3) शासन के पत्रांक: वी०आई०पी०-०६/सोलह-1-२०14 (रिट-३९)/२०14 में उद्धृत रिट याचिकाओं में कुलसचिव द्वारा पैरवी न किया जाना तथा जानबूझकर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र न दाखिल किया जाना, (4) सत्र २०14-15 में कुलसचिव के रूप में श्री तोमर द्वारा अपने स्तर से अनाधिकृत बैंक खाता खोलकर एवं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से इतर किसी अन्य वेबसाइट को शुरू करते हुए संस्थाओं से आँन-लाइन आवेदन प्राप्त किया जाना तथा अपनायी गई प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अधिनियम/विनियमों का अनुपालन न किया जाना। उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त श्री तोमर पर अष्टाचार एवं अन्शासनहीनता के भी आरोप थे।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने कुलसचिव श्री यू०एस० तोमर पर लगे आरोपों की जांच हेतु 5 नवम्बर 2015 को न्यायमूर्ति श्री एस०के० त्रिपाठी (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था जिसमें प्रो० गुरदीप सिंह बाहरी कुलपित डाँ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ एवं श्री सर्वेश चन्द्र मिश्रा सेवानिवृत्त आई०ए०एस० को सदस्य नामित किया गया था। राज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति को श्री यू०एस० तोमर कुलसचिव डाँ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के विरूद्ध वितीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जाँच करनी थी। जाँच के दायरे में श्री तोमर की कुलसचिव पद पर नियुक्ति का मामला भी सिम्मिलित था।

राज्यपाल ने 23 नवम्बर 2015 को श्री यू0एस0 तोमर को कुलसचिव पद से निलम्बित कर दिया था। श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित) के गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 31 मई 2017 को अपनी 483 पृष्ठीय अंतिम जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। जिसके पश्चात् राज्यपाल ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित) को उनके विरूद्ध गठित अंतिम जांच समिति की रिपोर्ट पर 15 जून 2017 तक उनका पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया था। श्री तोमर द्वारा राज्यपाल के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार करते हुए 14 जुलाई 2017 एवं 17 जुलाई 2017 को राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया था। श्री तोमर को सुनने के पश्चात् राज्यपाल ने 20 जुलाई को उन्हें अंतिम नोटिस जारी की थी।

----

अंजुम/ललित/राजभवन (288/4)